भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2993

15 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात प्राधिकरण

2993. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) में प्रचालन से समेकित राजस्व के प्रतिशत में पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत वर्ष की तुलना में जुलाई-सितंबर 2020 में लाभ अर्जित करने के बावजूद सेल में 10 प्रतिशत विनिवेश करने का क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की नई विनिवेश पहल में कंपनी की हिस्सेदारी को कितनी कीमत पर बेचा जा रहा है और कीमत निर्धारित करने की कार्यविधि और कारण क्या हैं;

(घ) क्या सेल की हिस्सेदारी की कीमत निर्धारित करने के लिए सरकार ने कोई व्यावसायिक परामर्श लिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची क्या है जिनका सरकार का भविष्य में विनिवेश करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के प्रचालन से चालू वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में राजस्व में वृद्धि हुई है, विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	प्रचालन से प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपए में)	पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत
पहली तिमाही 2020-21	9067	-
दूसरी तिमाही 2020-21	16924	87
तीसरी तिमाही 2020-21	19833	17

(ख) से (घ): जनता की शेयरधारिता को बढ़ाने और विनिवेश आय में बढ़ोतरी करने के लिए, सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की शेयरधारिता में से 10% हिस्से का स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के माध्यम से शेयरों के ऑफर फार सेल (ओएफएस) जिसे 64 रुपए/शेयर के आधार मूल्य पर दिनांक 14-15 जनवरी, 2021 को लाया गया था, द्वारा विनिवेश कर दिया है। आधार मूल्य के संबंध में व्यावसायिक मर्चेंट बैंकरों द्वारा लेन-देन के लिए की गई सिफारिशों पर यथोचित रूप से सोच-विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया।

(ड.): सरकार ने इस्पात मंत्रालय के अधीन एनएमडीसी लिमिटेड के नगरनार इस्पात संयंत्र, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तीन इकाइयों, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है।

****